

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुवैत सरकार महाराष्ट्र में एक उर्वरक कारखाना अर्थात् कुवैत मुरारजी उर्वरक परियोजना स्थापित करने को सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उमका व्यौरा क्या है; और

(ग) यह कारखाना कब तक चालू हो जायेगा और इसकी क्षमता कितनी होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) और (ख) . बम्बई के मैसर्स धर्मसी मोरारजी कैमिकल कम्पनी लिमिटेड ने सरकार को, महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में शेवा नहोवा नामक स्थान पर, मैसर्स पेट्रो-रमायन इण्डस्ट्रीज कम्पनी, कुवैत के सहयोग से 500,000 मीटरी टन डाईअमोनियम फास्फेट के उत्पादन के लिये कुवैत से आयात किये जाने वाले अमोनिया तथा मल्फर पर आधारित एक उर्वरक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में 115,000 मीटरी टन तरल अमोनिया तथा इससे सम्बद्ध 200,000 मीटरी टन मल्फर का वार्षिक आयात निहित है। कम्पनी को आशय-पत्र अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर दिया गया है कि यदि देशीय संसाधनों से नेफथा उपलब्ध हो गया तो, सरकार के कहने पर कम्पनी व्यापारिक उत्पादन की तारीख से आठवें वर्ष से नेफथा का इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। ऐसी एक शर्त से उपयुक्त हालात में देशीय पाइराइट्स से मल्फर का प्रतिस्थापन सुनिश्चित है।

(ग) परियोजना के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी का प्रश्न अभी विचाराधीन है। परियोजना के, सरकार द्वारा समस्त बातों के तय किये जाने के पश्चात्, दो वर्षों

की अवधि में पूरा हो जाने की आशा है।

चिकित्सा पाठ्यक्रमों में संशोधन

792. श्री देवराब पाटिल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा पाठ्य-क्रमों का संशोधन करके इन्हें देश की आवश्यकताओं के अनुरूप करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उम पर क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :
(क) और (ख) . चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर और खासकर राष्ट्रीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा पाठ्यचर्या में संशोधन, पाठ्यचर्या की एकरूपता की आवश्यकता, उपदेशात्मक और व्यावहारिक शिक्षण के बीच समय का अधि-भाजन, मेडिकल कालेजों में छात्रों का चयन, विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं और विश्व-विद्यालयों के बीच पारस्पर्य तथा चिकित्सा कालेजों में प्रवेश के मामले में निवास सम्बन्धी प्रतिबन्धों पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की है। इस समिति के सुभाव सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

राज्यों में सिंचाई की सुविधाएँ

793. श्री नारायणस्वरूप शर्मा :

कुमारी कमला कुमारी :

श्री रामस्वरूप बिद्यार्थी :

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या सिंचाई और बिद्युत मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत पांच वर्षों में नहरें बनाने, कुओं के खोदने और नलकूपों के लगाने में क्या प्रगति की है और विभिन्न राज्यों में प्रत्येक वर्ष कितनी अतिरिक्त भूमि में खेती की गयी;

(ख) 1969 में सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कितनी नहरें खोदी जायेंगी, कितने कुएँ और नलकूप लगाये जायेंगे और कितने एकड़ अतिरिक्त भूमि में खेती की जायेगी; और

(ग) सिंचाई के मामले में सरकार पिछड़े राज्यों को क्या विशेष सुविधायें उपलब्ध करेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विभिन्न राज्यों में पिछले 5 वर्षों के दौरान नहरों, कुओं और नलकूपों से लगभग 95 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है।

(ख) इन संसाधनों के जरिये 1969-70 में लगभग 20 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई करने का प्रस्ताव है।

(ग) चौथी योजना अवधि के दौरान राज्यों को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता का 10 प्रतिशत सिंचाई और बिजली की बृहत् परियोजनाओं के लिए पृथक रखने का प्रस्ताव है।

(ख)

गण्डक (उत्तर प्रदेश वाले भाग)
रामगंगा

गण्डक (उत्तर प्रदेश वाला भाग,
रामगंगा

उत्तर प्रदेश में बहुप्रयोजनीय तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

794. श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री बलराज मधोक :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय ऐसी चुनी हुई कौन-कौन सी बहुप्रयोजनीय तथा बड़ी परियोजनाएं हैं जिनके लिये केन्द्रीय सहायता दी जा रही है;

(ख) वे परियोजनाएं कितन स्थानों पर स्थित हैं और गत दो वर्षों में प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई;

(ग) उत्तर प्रदेश में चौथी पंचवर्षीय योजना में और कितनी सिंचाई परियोजनाएं चालू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना पर कितने व्यय का अनुमान है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दो परियोजनाओं—गण्डक (उत्तर प्रदेश वाले भाग) और रामगंगा—को पृथक रक्षित केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा रही है।

स्थान

गोरखपुर और देवरिया जिले
गढ़वाल जिले में कालागढ़ के पाम

पृथक रक्षित केन्द्रीय सहायता—लाख रुपयों में

1966-67

1967-68

370

475.33

*

1087

* रामगंगा परियोजना को केवल 1967-68 से ही पृथक रक्षित केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा रही है।